Merits of Green Revolution (Part - C)

B.A. (Part - 2)

Date 31/07/020
Page 1

हरित क्रान्ति से देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। खाद्यान्नों के उत्पादन में विशाल पैमाने पर वृद्धि हुई है जिससे देश खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ है और किसानों में आत्म-विश्वास जागा है। कृषि की आधुनिक तकनीक ने कृषक के दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया है। हरित क्रान्ति ने देश की कृषि व्यवस्था को अनेक लाभ दिये हैं जिसमें कुछ प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं :—

(1) **उत्पादन वृद्धि :—** हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप देश के कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है जिससे देश खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ है। गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का व चावल के उत्पादन में आशा से अधिक वृद्धि हुई है।

(2) **कृषि के प्राचीन पद्धतियों में परिवर्तन :→**

हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप कृषि के प्राचीन पद्धतियों को कृषकों ने छोड़ दिया है। कृषकों का एक बहुत बड़ा वर्ग यान्त्रिक खेती की ओर उन्मुख हुआ है। कृषि में ट्रैक्टर, विद्युत पम्पों, थ्रेशरों आदि का प्रयोग भारी मात्रा में होने लगा है।

(3) **कृषि के परम्परागत रूप में परिवर्तन :-**

हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप कृषि का

Scanned with CamScanner

परम्परागत रूप बदल गया है। उन्नत कृषक कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने लगा है। इससे पूर्व जब कृषक के पास समुचित साधन उपलब्ध नहीं थे, तब वह कृषि का उपयोग मात्र अपनी उदरपूर्ति के लिए करता था।

(4) रोजगार के अवसर बढ़े :— हरित क्रान्ति से देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हरित क्रांति से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं में लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है।

(5) खाद्यान्नों का आयात कम हुआ :— देश में खाद्यान्नों की आत्यधिक कमी के कारण प्रायः खाद्यान्न विदेशों से आयात करना पड़ता था। हरित क्रान्ति में बढ़े उत्पादन के कारण खाद्यान्नों का आयात लगभग बन्द कर दिया गया था। किन्तु देश में उपस्थित खाद्यान्न संकट के कारण खाद्यान्नों का आयात आज की हाल के वर्षों में भी करना पड़ा है।

(6) कृषि बचतें बढ़ीं :— खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होने से कृषक की बचतों में भी वृद्धि हुई है। इस बचत ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

Scanned with CamScanner

Demerits of Green Revolution

देश में हरित क्रान्ति के महत्व को लेकर विद्वानों के दो वर्ग हैं। विद्वानों का एक वर्ग हरित क्रान्ति का महत्व एवं उपलब्धियों को स्वीकार करता है, जबकि दूसरा वर्ग कृषि के इस नई व्यूह रचना का कट्टर आलोचक है। नई व्यूह रचना का समर्थन करने वाले विद्वानों में सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन का नाम प्रमुख है। डॉ० एम०एस० स्वामीनाथन का मत है कि "हरित क्रान्ति ने देश की कृषि योग्यताओं के प्रति विश्वास का वातावरण निर्मित किया है।"

उपर्युक्त समर्थक विद्वानों के विपरीत जो विद्वान हरित क्रान्ति के कट्टर आलोचक हैं, उनमें डॉ. एस० सी० तिवारी का नाम प्रमुख है। डॉ तिवारी का मत है कि "हरित क्रान्ति एक मिथ्या प्रयोग है क्योंकि यह न तो हरित है और न क्रान्ति ही है।" इस विफलता के अतिरिक्त, हरित क्रान्ति ने निम्न समस्याओं को भी जन्म दिया है:—

(1) **क्षेत्रीय असन्तुलन** :— अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम से क्षेत्रीय असन्तुलन में वृद्धि हुई है क्योंकि यह कार्यक्रम इन चुनिंदा क्षेत्रों में लागू किया गया है, जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(2.) **आर्थिक असमानताएं** :— हरित क्रान्ति ने

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विषमता बढ़ाई है। नई कृषि तकनीक का पूरा-पूरा लाभ केवल बड़े-बड़े किसान ही उठा पाये हैं। बहुधा उर्वर और सिंचित क्षेत्र बड़े किसानों के अधिकार में ही होता है तथा नये बीजों, कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों, उपकरणों और मशीनों को खरीदने की क्षमता भी उन्हीं में होती है। अतः छोटे और सीमान्त किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को हरित क्रान्ति का कोई लाभ नहीं मिल पाया है।

(3) कृषि में असंतुलन :— हरित क्रान्ति ने भारतीय कृषि में, विशेषकर खाद्य फसलों और वाणिज्यिक फसलों के बीच असंतुलन को जन्म दिया है।

(4) श्रम समस्याएँ :→ नई व्यूह रचना में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम समस्याओं को जन्म दिया है। उन्नत किस्मों के बीजों, उर्वरकों, नई उत्पादन तकनीक और बहु-फसलीकरण के उपयोग से कृषि की सघनता बढ़ी है। इससे श्रम की माँग और उसकी मजदूरी भी बढ़ी है।

(5) संस्थागत परिवर्तनों की उपेक्षा :→ नई व्यूह रचना में तकनीकी परिवर्तनों पर अधिक बल दिया गया है तथा संस्थागत परिवर्तनों की उपेक्षा की गई है।

Scanned with CamScanner

Suggestions for the Success of New Agriculture Policy.

हरित क्रान्ति की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझाव सरकार को दिए जा सकते हैं :→

(i) कृषि उत्पादन से सम्बन्धित सरकारी विभागों, पंचायतों, सरकारी समितियों व अन्य संस्थाओं में समन्वय होना चाहिए और नयी कृषि नीति की सफलता का उत्तरदायित्व इन्हें सौंपा जाना चाहिए।

(ii) अच्छी उपज के लिए उन्नत बीज, खाद और सिंचाई व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। इसके लिए उर्वरकों के वितरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और इसके प्रयोग का प्रशिक्षण किसानों को दिया जाना चाहिए।

(iii) फसल बीमा योजना शीघ्रता से लागू की जानी चाहिए।

(iv) कम ब्याज पर पर्याप्त मात्रा में समय पर ऋण दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) खाद्यान्नों के मूल्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। इससे होनेवाली अतिरिक्त आय आगे चलकर अधिक उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जा सकती है।

(vi) भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

The End

Scanned with CamScanner